पहले चरण में 10 क्लस्टर में विकसित होगा बीडा

मास्टर प्लान को मंजूरी मिलने के बाद कवायद तेज, डीपीआर तैयार करने के लिए तलाशी जा रही एजेंसी, 1500 करोड़ हो चुके हैं मंजूर

अमर उजाला ब्यूरो

झांसी। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) को जल्द जमीन पर उतारने की तैयारी है। बीडा के लिए चिह्नित भूभाग में विकास कार्य आरंभ होंगे। इसके लिए बीडा बोर्ड पहले ही 15 सौ करोड़ रुपये स्वीकृत कर चुका है। बीडा अफसरों के मुताबिक, क्लस्टर वार काम आरंभ कराए जाएंगे। प्रारंभिक दस क्लस्टर से शुरुआत होगी। डीपीआर तैयार करने के लिए एजेंसी की तलाश की जा रही है।

नोएडा की तर्ज पर झांसी में औद्योगिक नगरी बसाने के लिए 12 सितंबर 2023 को बीडा को मंजूरी दी गई थी। उसके बाद से अभी तक अफसर बीडा के भू-अर्जन में ही उलझे रहे। बीडा के प्रस्तावित स्थान पर कोई काम शुरू नहीं हो सका। हालांकि मास्टर प्लान भी तय न होने से यहां काम नहीं हो पा रहा था। कुछ दिन पहले बीडा बोर्ड ने कॉन्सेप्ट मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी।

विकास पथ पर बुंदेलखंड
अमर उजाला अभियान

यह मंजूरी मिलने के बाद अब बीडा में शुरुआती काम होंगे। अफसरों का कहना है आंतरिक परिवहन की सहूलियत के लिए 38 किलोमीटर लंबा लॉजिस्टिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। शुरुआती बसावट के लिए 400 हेक्टेयर जमीन चिह्नित हुई है। पहले चरण के विकास कार्य यहीं से आरंभ होंगे। इनके लिए 10 अलग-अलग क्लस्टर बनाए गए हैं। यहां कार्य कराने के लिए 1500 करोड़ रुपये भी मंजूर हो चुके। ओएसडी सौम्य मिश्रा के मुताबिक, डीपीआर बनाने के लिए कंपनी चयन का काम किया जा रहा है। इसके साथ बीडा की बसावट भी आरंभ होगी।

रेलवे का फ्रेट कॉरिडोर जोड़ने की भी योजना

बीडा को रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर से भी जोड़े जाने की योजना है। इसके जरिये माल ढुलाई आसान हो सकेगी। इसका प्रस्ताव भी बनाया गया है। इसके तैयार होने के साथ इसे सड़क समेत रेलमार्ग से भी जोड़ा जा सकेगा। बीडा अफसरों का कहना है कि खासतौर से दक्षिण एवं पश्चिमी हिस्सों को जोड़ने के लिए यह कवायद की जा रही है।

रफ्तार नहीं पकड़ रही बैनामों की रफ्तार

बीडा के लिए कराए जा रहे बैनामों की रफ्तार तेजी नहीं पकड़ पा रही। बीडा में करीब 22 हजार हेक्टेयर जमीन का बैनामा होना है, लेकिन अभी तक 4670 हेक्टेयर जमीन का ही बैनामा हो सका। इन बैनामों को कराने में 2098 करोड़ रुपये खर्च हुए। दूसरे चरण में 21 हजार एकड़ अतिरिक्त जमीन ली जानी है। बीडा अफसरों का कहना है कि लॉजिस्टिक कॉरिडोर की जरूरत के चलते दूसरे चरण के अधिग्रहण का काम तेजी से किया जा रहा है।